ECONSPEAK: A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences,
Vol. 2, Issue 9, September 2012 Impact Factor 2.809 ISSN: (2231-4571)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

भारत में आंतरिक प्रवास और शहरीकरण की भूमिका

डॉ0 केशरी नन्दन मिश्रा

सदस्य, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश

सारांश

आंदोलन मनुष्य की एक विशिष्ट विशेषता है, प्राचीन ऐतिहासिक साक्ष्यों से पता चलता है कि यह इस धरती पर उसकी उपस्थिति के बाद से मौजूद है। अब आधुनिक समय में प्रवास एक सार्वभौमिक घटना बन गया है। बढ़ता शहरीकरण एक महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन है जो पूरी दुनिया में हो रहा है, खासकर विकासशील देशों में। जबकि सीमा पार आप्रवासन पर शोधकर्ताओं और सरकारी निकायों का काफी ध्यान गया है, किसी देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर लोगों के आंतरिक प्रवासन पर नीतियों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। आर्थिक या अन्य कारणों से अपने सामान्य निवास स्थान से दूर लोगों का आंतरिक आंदोलन शहरी केंद्रों के विकास का प्रमुख कारण रहा है। ग्रामीण-से-शहरी प्रवास कई गुना बढ़ गया है, खासकर भारतीय समाज के कृषि से औद्योगिक से सेवा उन्मुख समाज में संक्रमण के बाद। इस घटना ने मौजूदा शहरों को सभी प्रवासियों को नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ भारतीय नागरिकों के रूप में उनके मौलिक अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करने में काफी दबाव डाला है।

आंतरिक प्रवास से संबंधित सभी प्रासंगिक पहलुओं - आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक - की पहचान करने की तत्काल आवश्यकता है। प्रवासन को जनसंख्या वृद्धि का सबसे अस्थिर घटक और आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारकों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील पाया गया है। जबकि सरकार ने प्रवासियों को मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ पहल की है, अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। पेपर महिलाओं और बच्चों के प्रवासियों से संबंधित मुद्दों को भी उजागर करेगा। यह पेपर उपर्युक्त पहलुओं पर विवरण एकत्र करने और सभी हितधारकों से सकारात्मक कार्रवाई को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है।

मूल शब्द: आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शहरीकरण, भारतीय समाज

प्रस्तावना

शहरी जनसंख्या में इस वृद्धि को तीन घटकों में विभाजित किया जा सकता है: शहरी क्षेत्रों में प्राकृतिक वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों का शहरी के रूप में पुनर्वर्गीकरण और ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में शुद्ध प्रवास। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में इन घटकों में से प्रत्येक के महत्व में उल्लेखनीय अंतर होगा। जनसंख्या अनुमानों पर किसी भी बातचीत में भारत और चीन दोनों प्रमुख रूप से केंद्र में हैं। चीन में, वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा देश, प्रवासन (और प्रशासनिक पुनर्वर्गीकरण) जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि की तुलना में शहरी विकास का एक बड़ा कारक है, बीसवीं शताब्दी के पिछले कुछ दशकों में मानव जीवन के विभिन्न आयामों में परिवर्तन की एक अभूतपूर्व लहर देखी गई है। तकनीकी प्रगति, वैश्वीकरण, औद्योगिक विस्तार, बढ़ती आबादी, और जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए आकांक्षाएं - इन सभी कारकों ने शहरी केंद्रों के विकास को जन्म दिया है, और लोगों को शहरी स्थानों पर

स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया है जो बेहतर संभावनाएं प्रदान करते हैं। इसने व्यापक ग्रामीण-शहरी प्रवास को देखा है, जिससे शहरी केंद्रों पर दबाव पड़ा है। शहरी क्षेत्रों को "समावेशी आर्थिक विकास के इंजन" के रूप में मान्यता दी गई है। 121 करोड़ भारतीयों में से 83.3 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जबकि 37.7 करोड़ शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, यानी लगभग 32% आबादी।

शहरीकरण क्या है?

मुख्य रूप से ग्रामीण से मुख्य रूप से शहरी में समाज के परिवर्तन की प्रक्रिया को 'शहरीकरण' कहा जाता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर बड़े पैमाने पर आबादी के प्रवास और कृषि व्यवसाय से अन्य व्यवसायों में जाने का संकेत देता है।

भारत में, 'शहरी' नामक क्षेत्र का अर्थ है कोई भी मानव बस्ती जिसमें 5000 से अधिक व्यक्ति रहते हैं, जिसका घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से अधिक है। और जहां 75% से अधिक पुरुष आबादी गैर-कृषि व्यवसायों में संलग्न है। सांविधिक नगर निगम, नगर समिति या नगर पंचायत या छावनी बोर्ड वाले ऐसे सभी नगरों को 'शहरी' क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

भारत की शहरी आबादी 2001 में लगभग 286 मिलियन से बढ़कर 2011 में 377 मिलियन हो गई है, और 2030 (भारत की जनगणना, 2011 और योजना आयोग, 2011) तक 600 मिलियन (1.4 बिलियन की कुल जनसंख्या में से) तक बढ़ने की उम्मीद है। स्वतंत्रता (1947) के बाद पहली बार, शहरी जनसंख्या वृद्धि (91 मिलियन) पिछले दशक (भारत की जनगणना, 2011) के भीतर ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि (90.5 मिलियन) से अधिक हो गई है।

भारत में शहरीकरण के कारण

भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान घटने लगा और द्वितीयक क्षेत्र से प्रतिशत योगदान में वृद्धि हुई। 1941 के बाद की अवधि में, भारत के चार महानगरीय शहरों का तेजी से विकास हुआ, जो कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई थे। औद्योगिक क्रांति के कारण देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि देखी गई और नई प्रौद्योगिकियों के आविष्कार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि की। सार्वजनिक क्षेत्र के विकास के परिणामस्वरूप सार्वजनिक परिवहन, सड़कों, जल आपूर्ति, बिजली, और इसलिए शहरी क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे का विकास हुआ।

1950 के बाद से कम आर्थिक रूप से विकसित देशों में शहरीकरण के तीन मुख्य कारण हैं:

1. ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के दबाव और संसाधनों की कमी के कारण ग्रामीण से शहरी प्रवास बड़े पैमाने पर हो रहा है। ये 'धक्का' कारक हैं।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शहर की ओर 'खींचा' जाता है। अक्सर वे मानते हैं कि शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी बेहतर होगा। वे आमतौर पर गलत होते हैं। लोग अच्छी तनख्वाह

वाली नौकरियों, आकस्मिक या 'अनौपचारिक' काम, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा को खोजने के अधिक से अधिक अवसरों की भी आशा करते हैं।

3. मृत्यु दर में कमी के कारण प्राकृतिक वृद्धि हुई है जबकि जन्म दर उच्च बनी हुई है।

शहरीकरण के परिणाम

हाल के वर्षों में, भारत में कई बदलावों के प्रवास के पैटर्न और गति पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। पिछले दो दशकों में विकास के पैटर्न ने कृषि और गैर-कृषि के बीच और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई को लगातार चौड़ा किया है, और यह लगातार कुछ क्षेत्रों और कुछ राज्यों में केंद्रित है। आर्थिक अवसरों में बढ़ती स्थानिक असमानताओं ने प्रवास की गति और पैटर्न पर भी अवश्य ही प्रभाव डाला होगा। असमान विकास और कृषि और उद्योग के बीच बढ़ता अंतर विकास के पैटर्न का एक आवश्यक सहवर्ती है।

शहरी विकास में चुनौतियां

शहरी शासन

74वें संशोधन अधिनियम को उन राज्यों द्वारा आधे-अधूरे ढंग से लागू किया गया है, जिन्होंने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को पूरी तरह से सशक्त नहीं बनाया है। यूएलबी में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत शामिल हैं, जिन्हें शहरी विकास के प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों द्वारा समर्थित किया जाना है। इसके लिए, यूएलबी को कार्यों, वित्तीय संसाधनों और स्वायत्तता के स्पष्ट प्रतिनिधिमंडल की आवश्यकता है। वर्तमान में शहरी विकास के लिए शहरी शासन में सुधार की आवश्यकता है, जो यूएलबी की प्रौद्योगिकी, प्रशासनिक और प्रबंधकीय क्षमता को बढ़ाकर किया जा सकता है।

योजना

योजना मुख्य रूप से केंद्रीकृत है और अब तक राज्य योजना बोर्ड और आयोग कोई विशिष्ट योजना रणनीति नहीं लेकर आए हैं जो इसके लिए योजना आयोग पर निर्भर है। वर्तमान सरकार में इसके बदलने की उम्मीद है, क्योंकि योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है और अब राज्यों को सशक्त बनाने और संघीय ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

वित्त

बड़ी चुनौती शहरी स्थानीय निकायों के साथ राजस्व सृजन की है। इस समस्या का विश्लेषण दो दृष्टिकोणों से किया जा सकता है। पहला, राज्यों ने यूएलबी को राजस्व उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त स्वायत्तता नहीं दी है और दूसरा कुछ मामलों में यूएलबी उन कर और शुल्क शक्तियों का भी उपयोग करने में विफल रहे हैं जिनके साथ उन्हें निहित किया गया है।

भारत में आंतरिक प्रवास

प्रवासन गतिशीलता का एक रूप है जिसमें लोग विभिन्न कारणों से परिभाषित प्रशासनिक सीमाओं के पार अपने आवासीय स्थान को बदलते हैं, जो अनैच्छिक या स्वैच्छिक या दोनों का मिश्रण हो सकता है। प्रवासी एक 'अस्थायी आबादी' का गठन करते हैं, क्योंकि वे अपने स्रोत और गंतव्य स्थानों पर रहने के बीच वैकल्पिक होते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में मात्रा और प्रवासन दर में वर्तमान वृद्धि मुख्य रूप से बढ़ती बेरोजगारी, गरीबी, कम मजदूरी, भूमि जोत के छोटे आकार, बुनियादी ढांचे के विकास और सुविधाओं की कमी, पर्यावरणीय गिरावट और प्राकृतिक संसाधनों की कमी, सीमित आजीविका विकल्पों के कारण है। ग्रामीण क्षेत्र। दूसरी ओर बेहतर रोजगार के अवसर, शैक्षिक अवसर, बेहतर चिकित्सा सेवाएं, मनोरंजन, उच्च मजदूरी, कम जोखिम भरा काम, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार; शहरी क्षेत्रों में बेहतर नागरिक सुविधाओं और सुविधाओं आदि ने ग्रामीण क्षेत्रों के प्रवासियों को आकर्षित किया है।

प्रवासन के कारण

भारत में महिला प्रवासन का सबसे महत्वपूर्ण कारण विवाह है, आधे से अधिक प्रवासियों के लिए साझा करना। यह महिलाओं के विवाह के बाद पति के स्थान पर प्रवास करने के सामाजिक रिवाज के कारण है।

रोजगार और व्यवसाय की आवश्यकता एक दसवें से अधिक प्रवासियों के लिए है, जबकि शिक्षा प्रवासन के कारण के रूप में सभी प्रवासियों का लगभग दो प्रतिशत है।

जनगणना में पलायन के लिए शिक्षा को एक कारण के रूप में शामिल किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो स्कूल या कॉलेज में शामिल होने के लिए चला गया है, इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। हालाँकि, जनगणना उन लोगों के बीच अंतर करती है जो शिक्षा के लिए स्वेच्छा से चले गए और जो परिवार के कमाने वाले सदस्य के साथ चले गए।

भारत में राजमार्गों के निर्माण, बड़ी सिंचाई परियोजनाओं और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कारण हजारों लोग विस्थापित हो रहे हैं। भारत की जनगणना इस मुद्दे से अवगत है, लेकिन इसके गणनाकारों को इसे अन्य श्रेणी (भगत 2005) में शामिल करने का निर्देश दिया।

निष्कर्ष

प्रवासन और शहरीकरण को वैश्विक शहरों के उद्भव के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए, जिनमें से कई ने हाल के वर्षों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ संबंध स्थापित करके जीवंतता हासिल कर ली है। भारत को व्यथित आंतरिक प्रवास के बारे में चिंतित होना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप बाद में बंधुआ मजदूरी और महिलाओं की तस्करी जैसी प्रथाएं होती हैं। मुख्यधारा के समाज में प्रवासियों का सामाजिक समावेश एक बड़ी चुनौती है जिसे भारत को संबोधित करने की आवश्यकता है क्योंकि स्थानीय लोग बाहरी लोगों को अपना नहीं मानते हैं। प्रवासन और शहरीकरण आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन का एक अभिन्न अंग हैं, और ऐतिहासिक अनुभव ने दिखाया है कि इसे रोका नहीं जा सकता है। प्रवासी सामाजिक रूप से गतिशील, सांस्कृतिक रूप से नवोन्मेषी और आर्थिक रूप से समृद्ध समाजों के अपरिहार्य और अदृश्य प्रमुख अभिनेता हैं।

सरकारों और स्थानीय निकायों की सभी नीतियों और कार्यक्रमों को ध्यान में रखना चाहिए। आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ते हुए, शहरीकरण आर्थिक विकास और विकास की एक अनिवार्य प्रक्रिया है। शहरी प्रधानता एक सकारात्मक कारक हो सकती है क्योंकि इसका परिणाम अर्थव्यवस्था को दिखाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की मात्रा पर पड़ता है। नीतिगत सिफारिश के साथ चर्चा का समापन करते हुए कि विकासशील राष्ट्रों को ग्रामीण क्षेत्रों से शहर में एक क्रमिक, संगठित प्रवासी को बढ़ावा देने के लिए आज जो भी राजनीतिक और आर्थिक शक्ति है, उसका उपयोग करना चाहिए। प्रक्रिया अपरिहार्य है, लेकिन स्थानीय जनता के सर्वोत्तम हित में इसे नियंत्रित किया जा सकता है

References

Appleyard, R.T. (Ed.) 1989 The Impact of International Migration on Developing Countries. Organization for Economic Cooperation and Development, Paris.

Bagat R.B. (2008). Assessing the measurement of Internal Migration in India. Asian and Pacific migration Journal Vol.17 No.1.

Byravan, S. and S. C. Rajan (2009); "Warming up to immigrants: An option for US climate policy", Economic and Political Weekly, 44, 19-23.

Census of India 2001. Soft copy, India D-series, Migration Tables. Registrar General and Census commisioner, India.

Deshingkar, P. and Farrington, J. (2009): 'Circular Migration and Multi locational Livelihood Strategies in Rural India', Oxford University Press, New Delhi.

Government of India. "Indian Labour Statistics" (various Issues), Labour Bureau, Ministry of Labour, Government of India.

Henderson, J. V. (1988); Urban development: Theory, fact and illusion. NY: Oxford University Press

Premi, M. K.(2006), Population of India: In the New Millennium: Census 2001, National Book Trust India, New Delhi.

Samhita chaudhuri (2012) - Urbanisation and urbanism: In the context of Environment and Culture of India – IJRSS Volume2 Issue-3.

Sustainable Urban Form for Indian cities (2011) - Research study series No.112 National Institute for urban affairs.